nwda.gov.in

वाटर विजन-2047 में नदियों के संरक्षण पर काम : पाटिल

आइजीएनसीए में तीन दिवसीय छठे नदी उत्सव का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार नदियों के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। वाटर विजन-2047 के तहत नदियों के संरक्षण को लेकर छोटी-मझोली और बड़ी योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। मानवीय हस्तक्षेप से नदियों को हुए नुकसान को भी ठीक करने करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। केंद्रीय जलशक्ति ने बृहस्पतिवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आइजीएनसीए) आयोजित तीन दिवसीय छठे नदी उत्सव का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी साझा की। उन्होंने इस अवसर पर पांचवें नदी उत्सव में पुरस्कृत शोध पत्रों के संकलन और पोर्टल का लोकार्पण किया।

आइजीएनसीए अध्यक्ष पद्मभूषण रामबहादुर राय सहित जल संरक्षणविद, कलाकार, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। इस मौके पर नदियों के प्रति श्रद्धा, उत्साह और जिम्मेदारी का पुनर्जनन करने के संकल्प दिलाते हुए गुरु सुधा रघुरामन ने शास्त्रीय गायन के साथ सभी अतिथियों को नदियों की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

नदी उत्सव के मुख्य अतिथि सीआर पाटिल ने नदियों को भारत की जीवनरेखा और संस्कृति का आधार बताते हुए उनके संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। आइजीएनसीए अध्यक्ष रामबहादुर राय ने यमुना सफाई और तटबंध निर्माण पर कार्यों की सराहना की। नदी उत्सव के शुभारंभ सत्र में 'रिवरस्केप डायनामिक्स' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई।

नदी उत्सव के शोध पत्रों के संकलन का लोकार्पण करते केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, आइजीएनसीए अध्यक्ष पद्मभूषण रामबहादुर राय व अन्य ● जागरण

जल प्रबंधन पर मनरेगा का 65% खर्च होगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने जल संचयन और प्रबंधन को स्थायी समाधान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में ऐतिहासिक संशोधन किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और संचयन कार्यों पर न्यूनतम व्यय अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ की।

कृषि मंत्री चौहान ने बताया कि अब 'अति जल संकटग्रस्त' प्रखंडों में जल प्रबंधन कार्यों पर न्यूनतम 65% राशि खर्च होगी।